

डोप टेस्ट

राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती से पहले उम्मीदवारों का डोप टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे चिट्ठे का सेवन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए गम्भीरता से काम कर रही है और हर जिले में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर पुलिस कांस्टेबल के साथ आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत सहायक की टीम गठित होगी।

जो भी पुलिस में भर्ती होगी, उसमें पहली स्टेज पर डोप टेस्ट, चिट्ठा का टेस्ट किया जाएगा। मेनली चिट्ठा का टेस्ट किया जाएगा और उसके बारे में हमने विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है पंचायतों में पांच और छह पंचायत पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगेगी, एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगेगी और एक पंचायत सेक्रेटरी को उसकी कार्य प्रणाली में उसको सम्मिलित किया जाएगा, पूरी रिपोर्ट्स मंगाई जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स है। उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहां उगाते आ रहे हैं, नशे में शराब भी आती है, सेवन भी आता है तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व यह बनता है जो चिट्ठा आ रहा है जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहां से आती है उसको हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है।

सिकंदर कुमार

सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा में सुधार का मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाया। इसके जवाब में केन्द्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारान्दलाजे ने बताया कि केन्द्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने सिकंदर कुमार को बताया कि केन्द्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को एक पोर्टल यानि ई-श्रम पर एकीकृत किया है।

जनऔषधि केन्द्र

केन्द्रीय उर्वरक व रसायन राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान लगभग 3 हजार 4 सौ 93 करोड़

रूप की दवाईयां जनऔषधि केन्द्रों के माध्यम से बेची गई हैं। राज्यसभा में सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 30 जून तक देशभर में कुल 16 हजार 9 सौ 12 जनऔषधि केन्द्र खोले गए हैं और इनके माध्यम से दवाईयां व चिकित्सा उपकरण 50 से 80 फीसदी सस्ती दरों पर बेचे जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। इस संबंध में नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि इसका लाभ अधिकतम किसानों तक पहुँचे। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए।

थुनाग कॉलेज

प्राकृतिक आपदा के बाद बागवानी व वानिकी महाविद्यालय थुनाग को स्थानांतरित करने के फैसले का छात्रों व अभिभावकों ने सरकार का समर्थन किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान अभिभावकों ने कहा कि उनकी मांग पर ही नाचन के लिए कॉलेज शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 जून की रात को भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से छात्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे और उन्हें दो दिन तक भोजन, पानी व अन्य जरूरी सुविधाओं की भारी कमी से जूझना पड़ा। आपदा के हालात इतने खराब थे कि 3 जुलाई को छात्रों को पैदल ही सुरक्षित स्थानों की ओर निकलना पड़ा।

मौसम

प्रदेश के अनेक भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम आज भी रुक-रुक कर जारी है। भूस्खलन के कारण राज्य में अभी भी एक राष्ट्रीय उच्चमार्ग सहित 3 सौ एक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। मंडी, कुल्लू राष्ट्रीय उच्चमार्ग बनाला-औट के पास भारी बारिश के कारण बंद है। इसके अलावा 4 सौ 36 बिजली ट्रांसफार्मर और 2 सौ 54 पेयजल योजनाएं भी ठप्प हैं। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में राज्य में एक सौ 70 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 36 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है।
